sभारत सरकार
सहकारिता मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न 237
मंगलवार, 22 जुलाई, 2025/31 आषाढ़,1947 (शक) को उत्तरार्थ

सहकारी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना

†237. **श्री बसवराज बोम्मईः**

क्या **सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सहकारी क्षेत्र में 'विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना' बनाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो इसकी वर्तमान स्थिति और इस पायलट परियोजना के पूरा होने की समय-सीमा सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा चिह्नित/गठित की जा रही प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पीएसीएस) की राज्य-वार संख्या कितनी है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने देश में सभी प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पीएसीएस) के कम्प्यूटरीकरण के लिए कोई कदम उठाए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार, विशेष रूप से कर्नाटक राज्य का, ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

सहकारिता मंत्री
(श्री अमित शाह)

(क) से (ख): जी हाँ, मान्यवर । सरकार ने दिनांक 31.05.2023 को "सहकारिता क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना" को मंजूरी दी है जिसे एक पायलट परियोजना के रूप में शुरू किया गया है । इस परियोजना में कृषि अवसंरचना कोष (AIF), कृषि विपणन अवसंरचना योजना (AMI), कृषि यांत्रिकीकरण पर उपमिशन (SMAM), प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना (PMFME), आदि जैसी भारत सरकार की विभिन्न मौजूदा योजनाओं के अभिसरण के माध्यम से पैक्स स्तर पर गोदामों, कस्टम हायरिंग केंद्रों, प्रसंस्करण इकाइयों, उचित मूल्य की दुकानों, इत्यादि सहित विभिन्न कृषि अवसंरचना का निर्माण शामिल है ।

इस योजना की पायलट परियोजना के अधीन 11 राज्यों के 11 PACS में गोदामों का निर्माण पूरा हो गया है । इसका राज्य-वार ब्योरा **अनुलग्नक -I** में संलग्न है । इसके अतिरिक्त, इस परियोजना के

अंतर्गत 500 से अधिक पैक्स की पहचान गोदाम निर्माण के लिए की गई है और दिसम्बर 2026 तक निर्माण कार्य पूर्ण करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

(ग): भारत सरकार ने पांच वर्षों की अवधि में देश की सभी पंचायतों और गांवों को आच्छादित करने के उद्देश्य से नए बहुउद्देशीय पैक्स/डेयरी/ मात्स्यिकी सहकारी समितियों की स्थापना की योजना को अनुमोदित किया है । यह पहल नाबार्ड, एनडीडीबी, एनएफडीबी और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों द्वारा समर्थित है । इस पहल के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए दिनांक 19.9.2024 को 'मार्गदर्शिका' का विमोचन किया गया, जो हितधारकों के लिए लक्ष्य और समय-सीमा निर्दिष्ट करती है । राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस के अनुसार दिनांक 15.02.2023 को योजना के अनुमोदन के बाद से दिनांक 30.06.2025 तक देश भर में कुल 22,933 नई बहुउद्देशीय पैक्स, डेयरी और मात्स्यिकी सहकारी समितियां पंजीकृत की गई हैं, जिनमें 5,937 बहुउद्देशीय पैक्स शामिल हैं। इस योजना के अनुमोदन के बाद से गठित बहुउद्देशीय पैक्स का राज्य-वार ब्योरा **अनुलग्नक-II** में दिया गया है ।

(घ) से (ङ): पैक्स को सुदृढ़ करने हेतु 2925.39 करोड़ रुपए के कुल वित्तीय परिव्यय से कार्यशील पैक्स के कम्प्यूटरीकरण की परियोजना को भारत सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया हैं, जिसमें देश के सभी कार्यशील पैक्स को कॉमन ERP आधारित राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर पर लाकर राज्य सहकारी बैंकों (StCBs) तथा जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों (DCCBs) के माध्यम से नाबार्ड से लिंक करना शामिल है । इस परियोजना के अधीन 31 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के कुल 73,492 पैक्स अनुमोदित किए गए हैं । 30 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा हार्डवेयर की खरीद कर ली गई है तथा कुल 59,920 पैक्स को ERP पर ऑनबोर्ड कर लिया गया है ।

पैक्स कम्प्यूटरीकरण परियोजना के अंतर्गत, कर्नाटक राज्य से कुल 5,628 पैक्स को संस्वीकृत किया गया है, जिनमें से 3,765 पैक्स को ईआरपी सॉफ्टवेयर पर ऑनबोर्ड किया गया है और 5,491 पैक्स को हार्डवेयर वितरित किए गए हैं । राज्यवार ब्योरा **अनुलग्नक -III** में संलग्न है ।

*****

अनुलग्नक -I

पायलट परियोजना के अंतर्गत निर्मित पैक्स गोदामों का विवरण

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	जिला	पैक्स का नाम	गोदाम की क्षमता (मीट्रिक टन)	निर्मित अवसंरचना
1.	महाराष्ट्र	अमरावती	नेरिपांगलाई विविध कार्यकारी सहकारी संस्था	3,000	गोदाम
2.	उत्तर प्रदेश	मिर्जापुर	बहुद्देश्यीय प्राथमिक ग्रामीण सहकारी समिति लिमिटेड, कोटवा पांडे	1,500	गोदाम
3.	मध्य प्रदेश	बालाघाट	बहुउद्देश्यीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसायटी मर्यादित, परसवाड़ा	500	गोदाम + धान प्राथमिक प्रसंस्करण इकाई
4.	गुजरात	अहमदाबाद	चंद्रनगर ग्रुप सेवा सहकारी मंडली लिमिटेड	750	गोदाम
5.	तमिलनाडु	थेनी	सिलामरथुपट्टी प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसायटी	1,000	गोदाम
6.	राजस्थान	श्री गंगानगर	घुमुडवाली ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड	250	गोदाम + बीज ग्रेडिंग इकाई + कस्टम हायरिंग सेंटर
7.	तेलंगाना	करीमनगर	प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड, गंभीरोपेट	500	गोदाम+ प्रसंस्करण इकाई
8.	कर्नाटक	बीदर	प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड, एकंबा	1,000	गोदाम+ प्रसंस्करण इकाई
9.	त्रिपुरा	गोमती	खिलपारा प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड	250	गोदाम + प्रसंस्करण इकाई + ग्रामीण हाट
10.	असम	कामरूप	2 नं. पब बोंगशर जी.पी.एस.एस. लिमिटेड	500	गोदाम
11.	उत्तराखंड	देहरादून	बहुद्देश्यीय किसान सेवा सहकारी समिति लिमिटेड, सहसपुर	500	गोदाम
	कुल			**9,750**	

अनुलग्नक – II

दिनांक 15.2.2023 के बाद नए गठित पैक्स का राज्य-वार ब्योरा

क्रम सं.	राज्य	पैक्स
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1
2	आंध्र प्रदेश	0
3	अरुणाचल प्रदेश	126
4	असम	238
5	बिहार	39
6	छत्तीसगढ़	0
7	गोवा	24
8	गुजरात	458
9	हरियाणा	21
10	हिमाचल प्रदेश	91
11	जम्मू और कश्मीर	161
12	झारखंड	45
13	कर्नाटक	180
14	लद्दाख	3
15	लक्षद्वीप	0
16	मध्य प्रदेश	199
17	महाराष्ट्र	177
18	मणिपुर	72
19	मेघालय	217
20	मिजोरम	41
21	नागालैंड	13
22	ओडिशा	1,534
23	पुडडुचेरी	3
24	पंजाब	0
25	राजस्थान	970
26	सिक्किम	24
27	तमिलनाडु	29
28	तेलंगाना	0
29	दादरा नगर हवेली तथा दमन और दीव	5
30	त्रिपुरा	187
31	उत्तर प्रदेश	516
32	उत्तराखंड	543
33	पश्चिम बंगाल	20
34	चंडीगढ़	0
35	दिल्ली	0
36	केरल	0
कुल योग		**5,937**

अनुलग्नक – III

पैक्स कम्प्यूटरीकरण परियोजना की स्थिति (30 जून 2025)

क्रम सं.	राज्य	अनुमोदित पैक्स	ईआरपी पर ऑनबोर्ड किए गए	ईआरपी पर गो लाइव	डे-एंड	संपरीक्षा पूर्ण	हार्डवेयर वितरित
1.	महाराष्ट्र	12,000	11,954	11,828	10,690	3,379	12,000
2.	राजस्थान	7,468	5,900	5,335	5,233	812	6,781
3.	गुजरात	5,754	5,627	4,513	4,082	2,046	5,754
4.	उत्तर प्रदेश	5,686	3,048	2,990	2,584	1,112	3,062
5.	**कर्नाटक**	**5,682**	**3,765**	**1,930**	**1,728**	**408**	**5,491**
6.	मध्य प्रदेश	5,188	4,428	4,491	4,272	4,062	4,534
7.	तमिलनाडु	4,532	4,531	4,529	4,528	27	4,532
8.	बिहार	4,495	4,460	4,444	4,431	3,299	4,477
9.	पश्चिम बंगाल	4,167	3,145	3,123	2,959	-	3,314
10.	पंजाब	3,482	3,408	2,217	2,080	7	3,456
11.	ओडिशा	2,711	-	-	-	-	-
12.	आंध्र प्रदेश	2,037	2,021	2,021	1,986	-	2,021
13.	छत्तीसगढ़	2,028	2,028	2,025	2,027	1,606	2,028
14.	हिमाचल प्रदेश	1,789	965	850	742	435	1,789
15.	झारखंड	2,797	1,414	1,479	1,424	1,272	1,500
16.	हरियाणा	710	609	582	433	6	710
17.	उत्तराखंड	670	670	669	588	-	670
18.	असम	583	579	573	442	166	583

19.	जम्मू और कश्मीर	537	536	534	536	530	537
20.	त्रिपुरा	268	207	193	195	166	268
21.	मणिपुर	232	175	170	169	81	169
22.	नागालैंड	231	64	48	18	2	231
23.	मेघालय	112	99	105	93	-	109
24.	सिक्किम	107	103	105	69	50	107
25.	गोवा	58	45	42	27	3	56
26.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	46	46	46	45	19	46
27.	पुडडुचेरी	45	43	44	42	3	45
28.	मिजोरम	49	25	25	22	22	25
29.	अरुणाचल प्रदेश	14	11	11	11	5	14
30.	लद्दाख	10	10	10	10	10	10
31.	दादरा नगर हवेली तथा दमन और दीव	4	4	4	4	3	4
	कुल	**73,492**	**59,920**	**54,936**	**51,470**	**19,531**	**64,323**

*****